(d) 50 per cent subsidy on the cost of fertilizer applied to plants in the field during the first three years to SC/ST growers.

(e) Financial assistance at rates varying between Rs. 1000 to Rs. 1500 per hectare to general category small growers and from Rs. 2200 to Rs. 4000 per hectare to SC/ST growers whose total area does not exceed 5.00 hectares.

(f) Financial assistance is also given for setting up irrigation facili-tits in rubber estates.

(g) Plantation requisites are also supplied to growers in non-traditional areas at concessional prices.

वानस्पतिक-ऊपादों का आयात

1482 श्री अजीत जोगी :

श्री मूलचन्द मीणा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वास्पतिक-उत्पादों के आयात संबंधी नियमों में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जून, 1991 से अब तक वानस्पतिक-उत्पादों के आयात से संबंधित कितने मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमलुद्दीन अहमद : (क) और (ख) आयात निर्यात नीति, 1992—97 (संशोधित संस्करण मार्च, 1993) के अंतर्गत गेहूं, धान, मोटे अनाज, दालों, तिल और बोने के लिए चारे की बीज का बिना लाइसेंस के आयात करने की अनुमति है बशर्ते कि बीज विकास पर नई नीति, 1988 की शर्तों को पूरा किया जाए और पौध, फल और बीज (भारत में आयात विनियमन) आदेश, 1989 के परमिट के अनुरूप हो। इसी प्रकार पौध, फल और बीज (भारत में आयात विनियमन) आदेश, 1989 के अंतर्गत सब्जियों के बीजों, फलों, फलों और पौधों फूल के कंदों और सकंदों, कटिंग, सैपलिंग तथा बोने और रोपण लिए फूलों और फलों में बुडयुड आदि बिना लाइसेंस के आयात करने की अनुमति है।

(ग) "वनस्पति संबंधी उत्पादों" के आयात के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

Proposal for an EPZ at Kanyakumari

1483. SHRI S. AUSTIN : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to start an Export Processing Zone at Kanyakumari;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES, CONSUMERS AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Taking into account the availability of funds and the need to optimise infrastructural facilities in the existing Export Processing Zones, it would not be possible at present for the Government to consider developing new Zones in the country.

Extension of Advance Licences of Exporters

1484. SHRI SURESH KALMADI :, Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Governmtnt have decided to grant extension of time for the advance licences of exporters who have fulfilled their export obligations before March 31 this year but could not realise the duty free imports; and